NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-10-2024

विषय सूची

155वीं महात्मा गांधी जयंती

भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए नीति आयोग का फ्रेमवर्क

PM ई-ड्राइव योजना

स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष

संक्षिप्त समाचार

अरुण नदी बेसिन का माउंट एवरेस्ट के उत्थान में योगदान

लाल बहादुर शास्त्री जयंती

स्टार्स (STARS) कार्यक्रम

भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक

भारत के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)

भारतीय इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी बोर्ड (IBBI)

SEBI ने वायदा और विकल्प (F-Os) नियम सख्त किये

फ्लोरोसेंट नैनोडायमंड्स (FNDs)

एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS)

155वीं महात्मा गांधी जयंती

सन्दर्भ

- 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है।
    - इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

महात्मा गांधी के बारे में

- महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
- वह एक भारतीय अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जो भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने।
- उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- **चंपारण सत्याग्रह (1917):** यह भारत में गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला महत्वपूर्ण अनुप्रयोग था, जहाँ उन्होंने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणालियों के विरुद्ध बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन किया।
- **खेड़ा सत्याग्रह (1918):** गांधी ने गुजरात में किसानों की सहायता के लिए एक अहिंसक आंदोलन का आयोजन किया, जो फसल विफलताओं और ब्रिटिश कराधान नीतियों के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे थे।
- **असहयोग आंदोलन (1920):** भारतीयों को ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया।
- **नमक मार्च (1930):** ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण विरोध, जहाँ गांधी ने समुद्री जल से नमक बनाने के लिए 240 मील की यात्रा की। अवज्ञा का यह कार्य भारत के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन (1942):** ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर एक सामूहिक विरोध, जिसके कारण पूरे भारत में, विशेष रूप से युवाओं के बीच व्यापक भागीदारी हुई।

गांधीजी की शिक्षाएं

- **अहिंसा:** उनका मानना था कि शांति और न्याय केवल अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
    - अहिंसा की उनकी व्याख्या शारीरिक कृत्यों से आगे बढ़कर विचार, भाषण और रिश्तों में अहिंसा को शामिल करती है।
- **सत्याग्रह:** इस सिद्धांत में सत्य और निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति शामिल है, जिसका उद्देश्य बिना किसी दबाव या आक्रामकता के न्याय प्राप्त करना है।
- **आत्म-पीड़ा:** गांधी का मानना था कि उत्पीड़क के हृदय परिवर्तन का मार्ग दूसरों को पीड़ा देने के बजाय खुद को पीड़ा सहने की इच्छा में निहित है।

- सत्याग्रही को उत्पीड़क पर नैतिक दबाव डालने के लिए शारीरिक, भावनात्मक या भौतिक कष्ट सहना चाहिए, जिससे उनके विश्वास की ताकत का पता चलता है।

- **सर्वोदय (सभी का कल्याण):** गांधी ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक कल्याण और उत्थान के महत्व पर बल दिया।
- **एकता और करुणा:** उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा दिया, लोगों से जाति, धर्म और नस्ल से ऊपर उठने का आग्रह किया।
- **सादा जीवन:** गांधीजी की जीवनशैली सादगी को प्रतिबिम्बित करती थी, तथा लोगों से भौतिक ज्यादतियों के बजाय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती थी।

साहित्यिक रचना

- हिंद स्वराज (1909)
- आत्मकथा: सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी
- समाचार पत्र: यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन।

महात्मा गांधी की विरासत

- सत्याग्रह (सत्य और अहिंसा) के उनके दर्शन ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, जिनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेता भी शामिल हैं।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के उनके प्रयासों के लिए गांधी को 1930 में टाइम पत्रिका का मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था।
- गांधी के प्रयासों से अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता मिली।

Source: PIB

भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए नीति आयोग का फ्रेमवर्क

समाचार में

- नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचे की सिफारिश की है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHE) क्या है?

- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHE) किसी बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति की महत्वपूर्ण घटना या आसन्न खतरे को संदर्भित करता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को काफी चोट या हानि का जोखिम उत्पन्न करता है।
- इसमें संक्रामक रोगों, जैविक विषाक्त पदार्थों, रासायनिक एजेंटों, परमाणु एजेंटों, विकिरण खतरों और बड़े पैमाने पर हताहतों या प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी स्थितियों से होने वाले खतरे शामिल हैं।

फ्रेमवर्क के बारे में

- महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया (PPER) फ्रेमवर्क एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) एवं प्रकोप के पहले 100 दिनों के अंदर त्वरित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों का समर्थन करता है।

- यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को महामारी तथा जैव आतंकवाद सहित स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर बनाने के लिए सशक्त करेगा।

- **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS):** रिपोर्ट में कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक EGoS बनाने का सुझाव दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की देख-रेख करेगा और गैर-आपातकालीन समय के दौरान प्रयासों की निगरानी करेगा।
  - यह समूह महामारी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करेगा और विभिन्न कार्यों के लिए उप-समितियाँ स्थापित करेगा।
  - अन्य सिफारिशों में रोग निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना, विशेष रूप से चमगादड़ प्रजातियों और कोविड-19 जैसी महामारियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों के कारण मानव-चमगादड़ इंटरफेस की निगरानी करना सम्मिलित है।
  - अनुसंधान संस्थानों और जीनोम अनुक्रमण केंद्रों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्रीय जैव सुरक्षा तथा जैव सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- **आपातकालीन वैक्सीन बैंक:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन प्राप्त करने के लिए आपातकालीन वैक्सीन बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया है।
- **महामारी विज्ञान पूर्वानुमान नेटवर्क:** संचरण की गतिशीलता की भविष्यवाणी करने और प्रतिवाद का आकलन करने के लिए एक नेटवर्क प्रस्तावित है, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले रोगजनकों के लिए निदान, उपचार एवं टीके विकसित करने पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) का एक नेटवर्क भी प्रस्तावित है।

वर्तमान परिदृश्य में महत्व

- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थितियाँ और आपदाएँ अंतरराष्ट्रीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, जिनके लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- इन खतरों से निपटने और उनसे उबरने के लिए समुदायों को तैयार करने के लिए प्रभावी आपदा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
- कोविड-19 महामारी ने वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति और आपदा प्रबंधन प्रणालियों की लचीलापन को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
  - महामारी की संभावना वाली आपदाओं और संक्रामक रोगों के लिए तैयारी करने और उनका जवाब देने के लिए राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक बहु-विषयक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं ?

- वन हेल्थ अप्रोच का तात्पर्य विशेष रूप से जूनोटिक रोगों, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) आदि में रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण क्षेत्रों के बीच समन्वय, सहयोग एवं संचार के लिए इंटरफेस से है।

मुद्दे और चिंताएँ

- महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897, तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA), 2005 में "महामारी" जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के लिए विशिष्ट परिभाषाओं का अभाव है और दवा/टीका प्रसार या संगरोध उपायों की प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

- नया फ्रेमवर्क भविष्य की महामारियों के लिए भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने, कोविड-19 के अनुभव से सीख लेने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक आधारभूत कदम के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय नियामक प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नियामक मानदंडों के वैश्विक सामंजस्य के महत्व को प्रकट करता है।
    - इससे विश्व भर में मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों द्वारा नियामक डेटा को स्वीकार करने में सुविधा होगी और नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए एक सामान्य फ्रेमवर्क स्थापित होगा, जिससे त्वरित आपातकालीन स्वीकृतियां संभव होंगी।

Source: IE

PM ई-ड्राइव योजना

सन्दर्भ

- सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए PM ई-ड्राइव योजना शुरू की है।
    - इसके तहत भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा।

PM ई-ड्राइव योजना के बारे में

- यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
- EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम) को PM ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।
- **सब्सिडी:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए इस योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है, लेकिन पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
    - दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
- ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों को पहले वर्ष में 25,000 रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे वर्ष में आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।
- L5 श्रेणी (कार्गो थ्री-व्हीलर) के लिए, उन्हें पहले वर्ष में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

- **e-वाउचर:** भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए EV खरीदारों के लिए e-वाउचर प्रस्तुत कर रहा है। एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, e-वाउचर जनरेट हो जाएगा।
    - योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए OEM (मूल उपकरण निर्माता) के लिए हस्ताक्षरित e-वाउचर आवश्यक होगा।
- **चार्जिंग स्टेशन:** यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर EV खरीदारों की रेंज चिंता को दूर करती है।
    - ये EVPCS उच्च EV पैठ वाले चुनिंदा शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) वह वाहन है जो आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर पर चलता है, जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करता है।
    - इसलिए, बढ़ते प्रदूषण, वैश्विक तापन, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि के मुद्दे को संबोधित करने के लिए इस तरह के वाहन को वर्तमान पीढ़ी के ऑटोमोबाइल के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ:

- **ऊर्जा दक्षता:** इलेक्ट्रिक मोटर आंतरिक दहन इंजन की तुलना में काफी अधिक कुशल हैं, जो ग्रिड से ऊर्जा के उच्च प्रतिशत को वाहन की गति में परिवर्तित करते हैं।
- **कम परिचालन लागत:** इलेक्ट्रिक वाहन की परिचालन लागत एक समान पेट्रोल या डीजल वाहन की तुलना में बहुत कम है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** EV शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है।
- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी:** EV तेल एवं गैस जैसे सीमित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं।
- **स्वास्थ्य लाभ:** वायु प्रदूषण को कम करके, EV सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से खराब वायु गुणवत्ता से जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की घटनाओं को कम कर सकते हैं।

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति

- **उद्देश्य:** इस क्षेत्र में सुचारू विकास को सुगम बनाना और 2030 तक निजी कारों में 30%, वाणिज्यिक कारों में 70%, बसों में 40% एवं दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में 80% तक EV की बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना।

- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP):** NEMMP को 2013 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- **फेम इंडिया योजना:** इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) इंडिया योजना को EV के विनिर्माण तथा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था।
- **GST में कमी:** भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए EV अधिक किफायती हो गए हैं।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** सरकार रेंज एंग्जायटी को दूर करने और EV अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर कार्य कर रही है।
- **निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन:** उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के अतिरिक्त, सरकार EV और उनके घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को सब्सिडी तथा प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **बैटरी स्वैपिंग नीति:** बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज सीमाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को लागू करने की संभावना खोज रही है, जहाँ EV मालिक जल्दी से पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी के लिए समाप्त हो चुकी बैटरी को बदल सकते हैं।
- ACC के निर्माण के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2021 में उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI योजना शुरू की गई थी।

अपनाने में चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती लागत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
- **सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भारत में EV को अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
- **रेंज एंग्जायटी:** रेंज एंग्जायटी, या चार्जिंग स्टेशन पर पहुँचने से पहले बैटरी चार्ज खत्म हो जाने का डर, EV पर विचार करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक सामान्य चिंता है।
- **बैटरी तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला:** भारत आयातित लिथियम-आयन बैटरी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और EV आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा:** भारत में कई उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता और समझ की कमी है, जिसमें उनके लाभ, तकनीक एवं उपलब्ध मॉडल शामिल हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आय स्तर, उपभोक्ता प्राथमिकताएँ और बुनियादी ढाँचे की असमानताएँ जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- भारत लिथियम-आयन बैटरियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में।

    - तेलंगाना जैसे राज्य भी भारत के EV विनिर्माण केंद्र बनने की आकांक्षा रखते हैं।
    - भारत का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों में लिथियम भंडार का दोहन करना भी है।
- सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए लिथियम की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

Source: BS

स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष

सन्दर्भ

- स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2024 को कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लेगा।
    - इस वर्ष का विषय, 'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता', स्वच्छता और पर्यावरण कल्याण के महत्व पर बल देता है।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 2014 में लॉन्च किया गया था।
- **लक्ष्य:** देश को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना।
- **शौचालय का बुनियादी ढांचा:** घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, साथ ही मलिन बस्तियों और प्रवासी जनसँख्या के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
- **व्यवहारिक परिवर्तन:** घर में शौचालयों के गंदे होने की पुरानी धारणा में बदलाव लाने के लिए, सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ कई कार्यक्रम चलाए, ताकि लोगों को ODF के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- इसमें दो उप-मिशन शामिल थे, शहरी और ग्रामीण या ग्रामीण (G)।
- SBM (G) का उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ODF), स्वच्छ और सैनेटाइज बनाना था।
    - 2019 में SBM (G) के पहले चरण का समापन हुआ, 2020-2021 में शुरू हुआ दूसरा चरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन और ODF की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयासों का विस्तार करता है।
    - **SBM (शहरी) 2.0:** 2020 में शुरू हुआ और 2025 तक चलने की उम्मीद है।
        - **लक्ष्य:** चरण 1 की उपलब्धियों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की सहायता से तरल एवं ठोस दोनों प्रकार के अपशिष्ट का उपचार किया जाए।

उपलब्धियाँ

- **बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डायरिया से संबंधित मृत्यु में उल्लेखनीय गिरावट की सूचना दी है, 2014 की तुलना में 2019 में 300,000 कम मृत्यु हुईं, जिसका श्रेय बेहतर स्वच्छता सुविधाओं को जाता है।
- इस मिशन ने मलेरिया, मृत जन्म दर और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वज़न वाले जन्म के मामलों में भी कमी लाने में योगदान दिया है।
- **शौचालय तक पहुँच में वृद्धि:** इस पहल ने 10 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालयों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जिससे 630,000 गाँवों में लगभग 50 मिलियन लोगों को लाभ हुआ है।
    - इनमें से विभिन्न गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।
- **महिलाओं के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा:** UNICEF की एक रिपोर्ट बताती है कि 93% महिलाएँ अपने घरों में शौचालय स्थापित करने के बाद सुरक्षित महसूस करती हैं।
- **परिवारों के लिए आर्थिक लाभ:** ODF गाँवों में रहने वाले परिवारों को औसतन 50,000 रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य-संबंधी बचत होती है।
- **भूजल प्रदूषण में कमी:** खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों में, मानव अपशिष्ट के कारण भूजल प्रदूषण का जोखिम 12.7 गुना कम है।
- **स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान:** इस पहल ने भारत के प्रतिष्ठित स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगमों और व्यक्तियों दोनों से समर्थन प्राप्त किया है।
- **स्वच्छता प्रयासों के लिए मान्यता:** देश भर के शहरों और कस्बों को उनकी स्वच्छता एवं सफाई उपलब्धियों के आधार पर 'स्वच्छ शहरों' का खिताब दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) में चुनौतियाँ

- **जागरूकता की कमी:** विभिन्न समुदायों में स्वच्छता प्रथाओं और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी है।
- **व्यवहार परिवर्तन:** स्वच्छता के बारे में लंबे समय से चली आ रही आदतों और सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलना मुश्किल है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
- **रखरखाव और स्थिरता:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निर्मित शौचालय और सुविधाएँ समय के साथ बनी रहें।
- **वित्त पोषण और संसाधन:** जबकि सरकारी सहायता उपस्थित है, चल रही पहलों, रखरखाव और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए लगातार वित्त पोषण की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** कई क्षेत्रों में अभी भी प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की कमी है, जिससे कूड़ा-करकट और प्रदूषण होता है।

- **क्षेत्र विशेष रणनीति का अभाव:** भारत के विविध भूगोल का मतलब है कि एक क्षेत्र में प्रभावी समाधान दूसरे में कार्य नहीं कर सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
- **निगरानी:** प्रगति और प्रभाव की प्रभावी निगरानी आवश्यक है, लेकिन इसे लगातार लागू करना मुश्किल हो सकता है।

आगे की राह

- स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई का मिशन नहीं है; यह भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख चालक है, जो बेहतर मानव पूंजी और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- SBM के कौशल पर ध्यान ने न केवल कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की है, बल्कि सतत सामुदायिक विकास के लिए एक खाका भी तैयार किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को लाभान्वित करता रहेगा।
- सरकार से निरंतर वित्त पोषण और समर्थन यह सुनिश्चित करेगा कि देश पिछले लाभों का लाभ उठा सके और यह सुनिश्चित करे कि पुराने तरीकों पर वापस न लौटें।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

अरुण नदी द्वारा बेसिन माउंट एवरेस्ट के उत्थान में योगदान

सन्दर्भ

- एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के आधार के पास स्थित अरुण नदी के कटाव के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में उत्थान हो रहा है।

परिचय

- एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित अरुण नदी, आस-पास के भूदृश्य को बनाती है और पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव को कम करती है।
- यह कटाव एक आइसोस्टेटिक रिबाउंड से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पृथ्वी की पपड़ी को ऊपर की ओर धकेलती है क्योंकि सामग्री हटा दी जाती है, जिससे माउंट एवरेस्ट और उसके पड़ोसी चोटियों का विकास होता है।
    - एवरेस्ट प्रति वर्ष लगभग दो मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है।
- **प्लेट टेक्टोनिक्स की भूमिका:** एवरेस्ट के उत्थान के पीछे प्राथमिक बल भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टेक्टोनिक टकराव है - एक घटना जो लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी।

अरुण नदी

- यह हिमालय में बहने वाली एक सीमा पार की नदी है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है।

- यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से निकलती है, जहाँ इसे फुंग चू या बुम-चू नदी के नाम से जाना जाता है।
- नेपाल से बहने के बाद, यह कोशी नदी में मिल जाती है, जो अंततः भारत में गंगा में मिल जाती है।

Source: IE

लाल बहादुर शास्त्री जयंती

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

लाल बहादुर शास्त्री

- **प्रारंभिक जीवन:** 2 अक्टूबर, 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में जन्मे।
- **शिक्षा और प्रभाव:** महात्मा गांधी के भारतीय राजकुमारों और ब्रिटिश शासन पर विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखने लगे।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी:** 16 वर्ष की आयु में, उन्होंने परिवार की अस्वीकृति के बावजूद अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
  - वे काशी विद्यापीठ में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की; "शास्त्री" की उपाधि प्राप्त की।
  - उन्होंने 1930 में नमक मार्च में उत्साहपूर्वक भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया।
  - अपनी सक्रियता के कारण कुल सात वर्ष तक जेल में रहे।
- **स्वतंत्रता के बाद की भूमिकाएँ:** अपने समर्पण और योग्यता के लिए पहचाने गए; 1946 में उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त हुए, बाद में गृह मंत्री बने।
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे, परिवहन और गृह मामलों सहित विभिन्न मंत्री पद संभाले।
  - उन्होंने एक बड़ी दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी जवाबदेही और ईमानदारी का पता चलता है।
  - उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल के माध्यम से 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- **विरासत और मूल्य:** अपनी ईमानदारी, विनम्रता और आंतरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं; एक ऐसे नेता के रूप में पहचाने जाते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को समझते थे।
- महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, उन्होंने कठोर मेहनत और नैतिक मूल्यों पर बल दिया, जो भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुणों को दर्शाता है।
- उन्होंने कठोर मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टि के साथ भारत को प्रगति की ओर अग्रसर किया।

Source: PIB

STARS कार्यक्रम

समाचार में

- स्टार्स परियोजना के लिए कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत की नींव रखने के लिए शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार के महत्व पर बल दिया।

राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण (STARS) कार्यक्रम के बारे में

- इसे अक्टूबर 2020 में कैबिनेट द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह 23 फरवरी, 2021 को प्रभावी हो गया और इसे वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

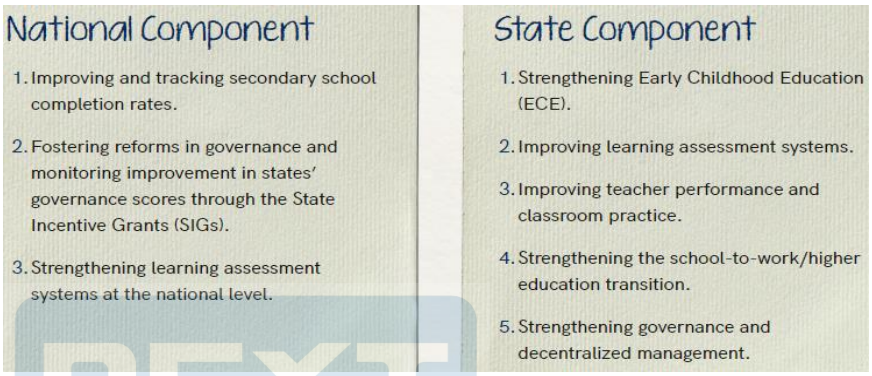

- यह हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार को बेहतर बनाने का समर्थन करता है।
- यह प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा, शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक प्रदर्शन और कक्षा अभ्यास, स्कूल से कार्यस्थल में संक्रमण और प्रशासन तथा बेहतर सेवा वितरण के लिए विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- यह भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना के साथ संरेखित है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख सिद्धांतों के संचालन का समर्थन कर रहा है।

Source: TOI

भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक

समाचार में

- भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह (MCSG) की 17वीं बैठक 1-2 अक्टूबर, 2024 को बर्लिन, जर्मनी में हुई।

भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह (MCSG) के बारे में

- MCSG भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ और जर्मनी के सशस्त्र बल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के बीच नियमित रणनीतिक तथा परिचालन चर्चाओं के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- बैठक की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई, जिसमें भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप सहायक प्रमुख और जर्मनी के उप निदेशक शामिल थे।
- चर्चा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करना था।
    - बैठक मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई।

Source:PIB

भारत के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट

सन्दर्भ

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में अगस्त में वार्षिक आधार पर 1.8% की गिरावट आई, जबकि जुलाई में इसमें 6.1% की वृद्धि हुई थी।

परिचय

- अगस्त में आठ में से केवल दो क्षेत्रों, उर्वरक और इस्पात, ने उत्पादन में क्रमिक वृद्धि दर्ज की।
- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और बिजली सभी का उत्पादन कम हुआ।
- ICI (आठ कोर उद्योगों का सूचकांक) उन उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन का संकेत देता है जो 'कोर' प्रकृति के हैं और इन आठ कोर उद्योगों में उत्पादन के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रदर्शन को मापता है।

कोर सेक्टर उद्योग कौन से हैं?

- इन कोर उद्योगों को अर्थव्यवस्था का मुख्य या प्रमुख उद्योग माना जाता है और ये अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं।
- आठ कोर सेक्टर उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं।
- आठ कोर उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% हिस्सा बनाते हैं।

Source: BS

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA).

सन्दर्भ

- प्रधान मंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह योजना आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।
- अभियान 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
- इसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने की परिकल्पना की गई है।
- मिशन में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जिन्हें 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
    - प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत उन्हें आवंटित धन के माध्यम से समयबद्ध तरीके से इससे संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

Source: PIB

भारतीय इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी बोर्ड(IBBI)

सन्दर्भ

- भारतीय इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी बोर्ड(IBBI) 1 अक्टूबर, 2024 को अपना आठवां वार्षिक दिवस मनाएगा।

परिचय

- यह इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी कोड, 2016 (कोड) के तहत 1 अक्टूबर, 2016 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- **कार्य:** इसकी प्राथमिक भूमिका भारत में इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी प्रक्रियाओं की देख-रेख करना, वित्तीय संकट का अधिक कुशल समाधान सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह इंसॉल्वेन्सी पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे नैतिक और पेशेवर मानकों का पालन करें।
- बोर्ड इंसॉल्वेन्सी एवं बैंककरप्सी से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है, पूरे भारत में ऐसी कार्यवाही के लिए एक समान ढाँचे को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

SEBI ने वायदा और विकल्प (F&Os) नियमों को कड़ा किया

सन्दर्भ

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स [F&Os या वायदा(Future) एवं विकल्प(option)] ट्रेडिंग के लिए प्रवेश बाधा बढ़ाकर मानदंड कठोर कर दिए हैं।

परिचय

- SEBI ने छह उपायों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं;
  - इंडेक्स वायदा और इंडेक्स विकल्पके लिए अनुबंध आकार को वर्तमान अनुबंध आकार 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करना,
  - साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों को युक्तिसंगत बनाना,
  - जिससे प्रत्येक एक्सचेंज को साप्ताहिक समाप्ति के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स में से केवल एक के लिए अनुबंध प्रदान करने की अनुमति मिल सके,
  - विकल्प खरीदारों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह,
  - पोजीशन सीमा की अन्तः दिवसीय निगरानी,
  - विकल्प समाप्ति के दिन टेल रिस्क कवरेज में वृद्धि, या किसी दुर्लभ घटना के कारण होने वाली हानि की संभावना, और
  - समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड उपचार को हटाना।

वायदा और विकल्प (F&Os)

- F&Os व्युत्पत्ति अनुबंध हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं जिनमें स्टॉक, कमोडिटीज, मुद्राएं आदि शामिल हैं।
- भविष्य में मूल्य संचलन की उनकी उम्मीद के आधार पर, निवेशक एक छोटी मार्जिन राशि का भुगतान करके परिसंपत्ति को 'लॉट' (एक लॉट में परिसंपत्ति की कई इकाइयां होती हैं) में खरीदने या बेचने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं।

वायदा अनुबंध

- वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक मानकीकृत समझौता है, जिसके तहत किसी परिसंपत्ति को किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विशिष्ट भविष्य की तिथि पर खरीदा या बेचा जाता है।
- खरीदार और विक्रेता दोनों को निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर अनुबंध निष्पादित करने की बाध्यता होती है।
- निवेशक केवल एक मार्जिन (कुल मूल्य का एक अंश) का अग्रिम भुगतान करते हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति की पूरी लागत का नहीं। अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ: स्टॉक, कमोडिटी, मुद्राएँ, आदि।

विकल्प अनुबंध

- विकल्प अनुबंध खरीदार को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं, कि वह अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले या उस दिन पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कोई परिसंपत्ति खरीद (कॉल विकल्प) या बेच (पुट विकल्प) सके।
- विकल्प के खरीदार के पास यह लचीलापन होता है कि अगर यह उनके लिए लाभदायक है तो वह अनुबंध का प्रयोग कर सकता है या अगर नहीं तो उसे समाप्त होने दे सकता है।
  - खरीदार इस अधिकार के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है।

Source: IE

फ्लोरोसेंट नैनोडायमंड्स(FNDs)

सन्दर्भ

- नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में, अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने उच्च निर्वात में फ्लोरोसेंट नैनोडायमंड्स (FNDs) को तैरते हुए तथा उन्हें बहुत तेजी से घूमते हुए देखा।

परिचय

- यह उद्योग में, विशेष रूप से सेंसर के रूप में, तथा मौलिक अनुसंधान में FND के बहुविध अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त करता है।

FNDs क्या हैं?

- वे कार्बन नैनोकणों से बने नैनोमीटर आकार के हीरे हैं, जो उच्च तापमान और उच्च दबाव प्रक्रिया में उत्पादित होते हैं।

- FNDs प्रकाश में स्थिर होते हैं और जीवित चीजों के लिए विषाक्त नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग, माइक्रोस्केल तापमान संवेदन तथा सहसंबंधी माइक्रोस्कोपी, आदि में कई अनुप्रयोग हैं।
- जीव विज्ञान में, वैज्ञानिक लंबी अवधि में कोशिकाओं और उनकी संतानों को ट्रैक करने के लिए FNDs का उपयोग करते हैं।

Source: TH

एकीकृत रक्षा स्टाफ(IDS)

सन्दर्भ

- मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) ने 01 अक्टूबर, 2024 को अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया।

परिचय

- मुख्यालय IDS की स्थापना 01 अक्टूबर, 2001 को तीनों सेनाओं की इकाई के रूप में की गई थी, जिसका आदर्श वाक्य था 'संयुक्तता के माध्यम से विजय'।
- **उद्देश्य:** उच्च स्तर पर रक्षा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करना, तथा विश्वसनीय एवं व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की खोज में तीनों सेनाओं और अन्य प्रासंगिक तत्वों को एकीकृत करना।

मुख्यालय IDS के तत्वावधान में प्रमुख उपलब्धियां

- एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली को अपनाना
- रक्षा नेटवर्क के निर्बाध एकीकरण और डेटा के दोहन के लिए संयुक्त संचार वास्तुकला,
- त्रि-सेवा उपग्रह पृथ्वी स्टेशन और IRNSS के साथ नाविक का एकीकरण,
- साइबरस्पेस संचालन और उभयचर संचालन आदि पर संयुक्त सिद्धांत।

Source: PIB

■■■■